रानी कमलापति या आदिवासियों का धृतराष्ट्र आलिंगन!

बादल सरोज

संघी कुनबे को भारत के मुक्ति आंदोलन के असाधारण नायक बिरसा मुण्डा की याद उनकी शहादत के 122वें वर्ष में आयी। अंग्रेजों से लड़ते हुए और इसी दौरान आदिवासी समाज को कुरीतियों से मुक्त कराते हुए महज 24 साल की उम्र में रांची की जेल में फांसी पर लटका दिए गए बिरसा मुण्डा के जन्मदिन 15 नवम्बर के दिन भाजपा आदिवासियों के लिए मार आकाश पाताल गुंजायमान मोड में दिखी। इस तरह दिखी कि पूरी तरह निजी कंपनी के हाथ में सौंपे जा चुके भोपाल के एक रेलवे स्टेशन-हबीबगंज- का नाम बदलकर खूब पुराने स्टेशन का पुन: उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी "मैं बचपन से ही अलाँ और फलां होना चाहता था" के फलां में आदिवासी जोड़कर खुद को बिरसा मुण्डा का नवावतार साबित करने पर आमादा नजर आये। यूँ यह सरासर आदिवासी और किसान विरोधी सरकार के घड़ियाली आँसू ही थे- मगर इस पर बाद में, पहले इनके इस दिखावे की असलियत जान लेते हैं।

कोई 52 करोड़ (कुछ के मुताबिक़ करीब 100 करोड़ रूपये) के सरकारी खर्च से जम्बूरी मैदान में हुयी यह जमूरागीरी एक त्रासद प्रहसन थी। चोर चोरी से भी न जाएगा और हेराफेरी के साथ ठगी भी करेगा की तर्ज पर इस बीच, इस बहाने मुस्लिम विरोधी संघी एजेंडे को भी पूरे जोर शोर से लागू किया जा रहा था। इतिहास के साथ हेराफेरी संघी कुनबे का प्रिय शगल है। वैसे देखा जाए तो यह उनकी जन्मजात मजबूरी भी है क्योंकि भारत के 5-7 हजार वर्षों के लिखित इतिहास में ऐसा एक भी ङ्क जी हाँ, मनु के अलावा एक भी-नहीं है जिसे ये अपना कह सकें। यही वजह है कि ये पुरखे उधार लेने की हड़बड़ी में मारे मारे फिरते हैं और उस फ़िराक में प्रामाणिक इतिहास में भी गड़बड़ी करने से बाज नहीं आते। पूरी तरह निजी कम्पनी को सौंपे गए देश के पहले तथाकथित वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति किया जाना भी इसी तिकड़म का हिस्सा है।

तीन सदी पुरानी रानी कमलापति की कहानी दिलचस्प है।

सोलहवीं सत्रहवीं सदी में बाकी पूरे मध्यभारत की तरह आज का भोपाल भी गोंड राजाओं के राज में था। गिन्नौरगढ़ के निज़ाम शाह इसके राजा थे। रानी कमलापति उनकी अनेक (कुछ के मुताबिक़) रानियों में से एक थीं- उनका व्यक्तित्व इतना भव्य था कि उसे विशाल भोपाल ताल से जोड़कर कहावत में आज भी याद किया जाता है कि ताल में भोपाल ताल बाकी सब तलैया / रानी तो कमलापति बाकी सब रनैया!! हुआ कुछ यूं कि राजदरबारों की साजिशों और षड्यंत्रों का शिकार बनाकर निज़ाम शाह मार डाले गए, युवा विधवा रानी कमलापति अपनी और अपने छोटे बच्चे की जान की खातिर जैसे तैसे वहां से बचकर आज के भोपाल गाँव में पहुँची।

उन दिनों इस इलाके में इस्लामपुर में अफगानी सरदार दोस्त मोहम्मद खान का मुकाम हुआ करता था। रानी कमलापति ने उन्हें राखी भेजकर अपना भाई बनाया और मुसलमान दोस्त मोहम्मद की मदद से अपने पति की हत्या करने वालों से बदला लेकर बदले में भोपाल उसे सौंप दिया। इतिहासकारों के मुताबिक़ दोस्त मोहम्मद ने भाई का यह रिश्ता आखिर तक निबाहा और इधर गोंड राजा भूपाल सिंह के नाम से बने भूपाल (रेलवे स्टेशन का पुराना नाम भूपाल ही था, उच्चारण में कठिनाई के चलते इसे अंग्रेजों ने भोपाल कर दिया) बसाया, उधर अपनी बहन बनी कमलापति को एक सुन्दर सा महल बनाकर दिया, जहां उसने अपने बाकी के दिन गुजारे।

संघी और भाजपाई अब इस इतिहास को बदलना चाहते हैं। आज जो हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापति करके आदिवासियों के सम्मान का दावा कर रहे हैं इन्हीं ने कुछ साल पहले गोंड राजा भूपाल के नाम वाले भोपाल का नाम बदलकर भोजपुर करने की कोशिश की थी। यह अलग बात है कि भोपाली अवाम ने एकजुट होकर इस हरकत को नाकाम कर दिया था। भाजपाई एजेंडा आदिवासियों की अस्मिता का सम्मान नहीं- उनका धृतराष्ट्रआलिंगन करने का है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने ट्वीट में इसे साफ़ भी कर दिया जब उन्होंने दावा किया कि "कमलापति भोपाल की आख़िरी हिन्दू रानी थीं।" इस तरह स्टेशन का नाम बदलना आदिवासियों को सम्मानित करने की नहीं उनके हिन्दूकरण की संघी मुहिम का हिस्सा है। आदिवासियों के प्रति उनका रुख क्या है यह प्रधानमंत्री द्वारा निजी कंपनी के रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के ठीक एक दिन पहले ही शिवपुरी के गाँव सैंकरा में पहुँची हरिलाल की लाश बयान कर रही थी। अति गरीब सहरिया आदिवासी हरिलाल ने दीवाली से पहले अपनी मजदूरी का बकाया पैसा माँगा तो दबंगों ने घर में बंद करके लाठियों और कुल्हाड़ी से उसकी पिटाई लगाकर अधमरा करके छोड़ दिया था। भाजपा राज की पुलिस ने हरिलाल की रिपोर्ट कुछ मामूली धाराओं

में दर्ज कर दबंगों की हिमायत की कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद हरिलाल नहीं उनकी लाश ही घर लौटी। इस गाँव के आदिवासियों को भरकर मोदी की सभा में लाने के लिए बसें भेजी गयी थीं- जिन्हे इस मौत से दु:खी और गुस्साए आदिवासियों ने खाली वापस लौटा दिया। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी - आदिवासियों और दलितों के उत्पीड़न, जिसमें हत्या, बलात्कार भी शामिल हैं, के मामले में मध्यप्रदेश, टॉप पर बैठे योगी के यूपी से थोड़ा सा ही नीचे है।

मोदी जिन आदिवासियों की "अब तक हुयी उपेक्षा" का राग भैरव जिस मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में सुना रहे थे, उस मध्यप्रदेश में आदिवासी बच्चों की शिशु मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा, राष्ट्रीय औसत 40 के मुकाबले 111 है। आदिवासी अवाम की गरीबी में भी सबसे आगे मध्यप्रदेश है तो बेरोजगारी में भी सबसे ऊपर मध्यप्रदेश के आदिवासी हैं। तीन साल पहले राज्यसभा में खुद मोदी के मंत्री ने स्वीकारा था कि रोजगार के लायक 69 प्रतिशत आदिवासी बेरोजगार हैं। उसके बाद कोरोना काल के दो वर्षों में क्या हुआ इसे औरंगाबाद की रेल पटरियों पर अपने खून को स्याही, बची रोटियों को कलम और खुद की देह को कागज़ बनाकर मध्यप्रदेश के आदिवासी दुनिया को बता चुके हैं।

ये वही भारत के आदिवासी और बिरसा मुण्डा, सिद्दू कान्हू मुर्मू , टांटिया भील, वीर नारायण सिंह, अलूरी सीताराम राजू, रानी गाइदिन्लयू और बादल भोई के वारिस हैं जिन्हे लुभाने के लिए रेलवे के लिए नवाब हबीब मियाँ की दान की जमीन पर बने हबीबगंज स्टेशन पर 49 प्रतिशत अमेरिकी कंपनी की पार्टनरशिप के साथ बंसल ग्रुप के कब्जे पर ठप्पा लगाने प्रधानमंत्री मोदी स्वयं आये थे। वही आदिवासी जिनकी सभ्यता के पूर्व से जो उनकी बसाहट है उन जंगलों को मध्यप्रदेश सरकार कंपनियों को सौंपने का फैसला पिछले महीने ही ले चुकी है। सरकार और कंपनियों के बीच हुए समझौतों में दर्ज होगा कि सरकार ये वन इन कंपनियों को आदिवासियों से खाली कराकर सौंपेगी।

गरीबों, उसमें भी आदिवासियों से, भाजपा की नफ़रत आज की नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय 30 मई 2002 को आदेश जारी कर आदिवासियों और वनवासियों को वनभूमि से बेदखल करने का आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में यहां तक था कि उनकी बेदखली और उनकी बसाहटों को तोड़ने फोड़ने पर जो खर्चा आएगा उसे भी इन्हीं आदिवासियों से वसूला जाएगा। यही खतरनाक आदेश था जिसे रद्द करवाकर यूपीए प्रथम के कार्यकाल में आदिवासी वनाधिकार क़ानून 2006 बनवाने में सीपीएम की नुमाईंदगी वाले वामपंथ ने पूरी ताकत लगा दी थी। दो साल पहले 2019 में सुप्रीम कोर्ट के मोदी चारण जज अरुण मिश्रा ने फिर करोड़ों आदिवासियों की बेदखली का आदेश सुनाया था। जिसे जबरदस्त देशव्यापी प्रतिरोध के बाद रुकवाया गया।

करें गली में कत्ल बैठ चौराहे पर रोयें की संघी-मोदी अदा आम अवाम के साथ अब आदिवासी भी समझने लगे हैं। उन्हें पता है कि भाजपा देश की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो आदिवासियों के अस्तित्व को ही स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है-वह उन्हें आदिवासी कहने तक को तैयार नहीं है, वनवासी कहती है और अपने कार्पोरेटी आकाओं के मुनाफे की तिजोरियां भरने के लिए उन्हें उनकी परम्परागत बसाहटों से खदेड़ कर कोलम्बस के अमरीका के आदिवासियों की दशा में पहुंचाना चाहती है। वे समझते हैं कि पहले नमस्कार कर पाँव छूना फिर मारना इन संघी-भाजपाईयों की ख़ास रणनीति है।

यही वजह थी कि मुफ्त की सरकारी बसें, 500 रुपयों की दिहाड़ी, रास्ते भर भोजन के इंतजाम और प्रधानमंत्री से मिलवाने के झांसे के बावजूद जितने का दावा किया गया था उसका 40 प्रतिशत भी नहीं आये। उन्हें मालूम है कि आदिवासी सीटों को जीतने की उम्मीद में यह धोखे की आड़ खड़ी की जा रही है, जैसे राजभर वोटों को लुभाने के लिए आज़मगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम राजा सुहेलदेव के नाम पर रखा जा रहा है उसी तरह हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर करने का झुनझुना भोपाल में बजाया जा रहा है। उन्हें, साल भर से दिल्ली की सीमाओं पर मोर्चा बनाये अपने किसान भाईयों की तरह पता है कि बिना बिरसा मुण्डा की तर्ज पर संगठित हुए और उलगुलान मचाये न उन्हें कुछ मिलेगा, न ही वे सलामत रहेंगे।

ठीक यही सन्देश था जो सिलगेर में अपने धरने को लगातार जारी रखके आदिवासी दे रहे हैं। धरना अभी भी जारी है। सिलगेर छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले में स्थित है, जहां इसी साल 14-15 मई की रात को पुलिस कैम्प स्थापित कर दिया गया। ग्रामीण आज तक इसका शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे हैं।

18 मई को पुलिस गोलीबारी में 4 आदिवासियों की मौत के बावजूद आदिवासी डटे हैं और 26 नवंबर को देशव्यापी किसान आंदोलन की पहली साल पूरी होने पर देश भर में किये जा रहे प्रदर्शनों में भी शामिल होने जा रहे हैं।

बिरसा मुंडा का उलगुलान कंपनीराज के खिलाफ था

विशद कुमार

बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर झारखंड के रांची के बगईचा में जुटे देश भर से आये आदिवासी आन्दोलनकारी संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित 'आदिवासी अधिकार कन्वेंशन' को संबोधित करते हुए भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि जिस कंपनीराज के खिलाफ बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था, आज मोदी जी झारखण्ड समेत देश के आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन और उनके खनिज व प्राकृतिक संसाधनों को अडानी-अम्बानी कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले कर उसी को थोप रहे हैं।

यहां तक कि बिरसा मुंडा जयंती को भी 'जन जातीय गौरव दिवस 'मनाने के नाम पर आदिवासियत की पहचान को नहीं रहने देना चाहते हैं। जल, जंगल और खनिज की कॉर्पोरेटी लूट के लिए ही आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में तमाम मुद्दों पर जारी संघर्षों के बड़े समन्वय और बड़ी लड़ाई की जरूरत है। जिसे विकसित करने और आन्दोलन को बल पहुंचाने में उनकी पार्टी हर स्तर पर मजबूत सहयोगी की भूमिका निभाएगी।

बता दें कि महानायक बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखण्ड समेत देश भर जारी आन्दोलनों के बीच समन्वय हेतु गठित 'आदिवासी संघर्ष मोर्चा 'द्वारा बगईचा में राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी अधिकार कन्वेंशन का आयोजन किया गया। जिसमें झारखण्ड, ओड़िशा, असम, कर्नाटक, गुजरात, छात्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु

और पश्चिम बंगाल समेत 14 राज्यों के 150 से अधिक आदिवासी प्रातिनिधियों ने भाग लिया। बगईचा में आयोजित इस कन्वेंशन की शुरुआत बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण और झारखण्ड जन संस्कृति मंच द्वारा प्रस्तुत उलगुलान गीत से की गयी।

अवसर पर आन्दोलनकारी दयामनी बारला ने कहा कि बिरसा मुंडा उलगुलान से भी अधिक चुनौतीपूर्ण स्थिति बनायी जा रही है। मोदी जी मन की बात में बिरसा मुंडा का गुणगान और 'जन जातीय गौरव ' की बात करते हैं तो दूसरी ओर, जिन आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन के अधिकार के लिए बिरसा मुंडा लड़े आज उनकी जमीनों को डिजिटल इंडिया के नाम पर ड्रोन सर्वे के जरिये हड़पने की साजिश भी चला रहे हैं। आज आदिवासियों को फिर से अपनी जमीनें बचाने की लड़ाई के लिए एकजुट होना होगा। आदिवासी बुद्धिजीवी प्रेमचंद मुर्मू ने कहा कि जब संविधान की शपथ लेकर शासन करने वाले सिरे से उसे व्यवहार में खारिज कर आदिवासी अधिकारों को निरस्त कर रहे हैं तो हमें भी अपने सभी अधिकारों के प्रति जागरूकता और एकजुटता बढ़ानी होगी।

कन्वेंशन की ओर से देवकी नंदन बेदिया ने आदिवासी मुद्दों का प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर झारखण्ड से वाल्टर कंडूलना, जेरोम जेराल्ड व गौतम सिंह मुंडा के अलावा विभिन्न राज्यों के दर्जनों प्रतिनिधियों ने विचार रखा। सम्मलेन से देशव्यापी आदिवासी आन्दोलन के 30 सूत्री मुद्दों का चार्टर पारित कर आन्दोलन की रूप रेखा तय की गयी।

कन्वेंशन संचालन के लिए प्रतिमा इन्नपी व रवि फान्चो (कार्बी आन्गालंग,असम), तिरुपति गोमंगो (ओड़िसा), सुमंती तिग्गा (चाय बगान, सिलीगुड़ी), देवकी नंदन बेदिया व जेवियर कुजूर को अध्यक्ष मंडल का सदस्य चुना गया। कन्वेंशन ने दयामनी बारला , देवकीनंदन बेदिया व जेवियर कुजूर समेत 19 सदस्यीय राष्ट्रीय संयोजन समिति, 41 सदसीय राष्ट्रीय परिषद् का चुनाव किया। असम के डा. जयंत रांगपी, प्रेमचंद मुर्मू व वाल्टर कंडूलना समेत 5 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार मंडल तथा सॉलीडैरिटी टीम का गठन किया गया।

इसके पूर्व 14 नवम्बर को कन्वेंशन के उद्घाटन सत्र में झारखण्ड जन संस्कृति मंच की प्रेरणा, मांदर, सेंगेल व अन्जोम संताली टीमों द्वारा आदिवासी जन गीत व नृत्य की भव्य प्रस्तुति कि गयी। इस अवसर पर चर्चित फिल्मकार श्रीप्रकाश निर्मित शहीद कामरेड महेंद्र सिंह पर आधारित डाक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

निजीकरण के ऐसे ही साइड इफेक्ट्स

क्या आप जानते है कि भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उद्घाटन किया उस रेलवे स्टेशन का 49 प्रतिशत मालिकाना हक एक विदेशी कम्पनी इंटरअप इंक के पास है ?

जी हाँ यह सच है ! नीजिकरण के ऐसे ही साइड इफेक्ट्स होते हैं कब कम्पनिया देशी से विदेशी बन जाए पता ही नहीं चलेगा !..... दरअसल जिसे नए भारत का नया रेलवे स्टेशन बताया जा रहा है वह भारत का सबसे पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है. यह स्टेशन पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर आधारित है.

इसी साल अगस्त में दैनिक भास्कर में एक खबर छपी कि अमेरिकी फंड हाउस इंटरअप इंक ने भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को डेवलप कर रही बंसल पाथवे में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी 915 करोड़ रुपए में खरीद ली है, अमेरिकी ग्रुप इंटरअप ने बंसलपाथवे का मूल्यांकन 1870 करोड़ रुपए आंका था और 915 करोड़ रुपए देकर उसने ग्रुप में 49 हिस्सेदारी हासिल कर ली है, यानी टेक्निकली जो भी बंसल पाथवे की प्रॉपर्टी है उसमें अमेरिकी ग्रुप इंटरअप इंक की 49 प्रतिशत भागीदारी है, इस खरीद को मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा था लेकिन मीडिया अब आपको यह तथ्य बताना भूल गया वैसे इस अमेरिकी ग्रुप इंटरअप्स इंक का रिकॉर्ड भी संदिग्ध है यदि कोई पत्रकार ढंग से इस कम्पनी की छानबीन करे तो ओर भी कई हैरतअंगेज जानकारियां सामने आ सकती हैं।

मार्च 2017 को भारतीय रेलवे द्वारा मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित हबीबगंज को पूर्ण रूप से पहले निजी रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया गया। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशन की देख-रेख के समस्त अधिकार प्राइवेट कम्पनी बंसल ग्रुप को सौंपे गये. और रेलवे स्टेशन से लगी बेशकीमती जमीन बंसल ग्रुप के हवाले कर दी गयी कांट्रेक्ट के अनुसार इस निजी रेलवे स्टेशन पर रेलवे केवल गाड़ियों का संचालन करेगी तथा पूरे रेलवे स्टेशन का संचालन प्राइवेट कंपनी बंसल ग्रुप करेगा, इस समझौते के अनुसार हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों की पार्किंग से लेकर खान-पान तक बंसल ग्रुप के अधीन है बंसल ग्रुप को रेलवे स्टेशन की जमीन की कमर्शियल स्पेस की लीज 45 साल के लिए मिली है

बंसल ग्रुप के साथ पीपीपी मॉडल पर समझौते के तहत तीन वर्ष में बंसल हैथवे को इस रेलवे स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करना था यानी मार्च 2020 तक यह तैयार हो जाना था लेकिन यह प्रोजेक्ट लेट हो गया और नवम्बर 2021 में यह पूरा तैयार हुआ है। 2018 में जैसे ही इस बंसल ग्रुप ने रिडेवलपमेंट के लिए जैसे ही रेलवे स्टेशन का अधिपत्य हासिल किया उसने हबीबगंज स्टेशन पर पार्किंग के रेट अचानक पांच गुना तक बढ़ा दिए उसने 24 घण्टे के लिए दो पहिया वाहन चालकों से रेलवे स्टेशन में पार्किंग के 235 रुपए और चार पहिया वाहन चालकों से 590 रुपए वसूलने शुरू कर दिए, बाद में जनप्रतिनिधियों ने रेलवे विभाग से इसकी शिकायत की तब रेट कम किया गया, इतना ही नही बंसल पाथवे हबीबगंज लिमिटेड द्वारा हबीबगंज स्टेशन परिसर में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट निर्माण के लिए मंजूरी से अधिक खुदाई की गयी, इस शिकायत पर खनिज विभाग द्वारा जांच की गई तो पाया कि कंपनी के पास 2 हजार घनफीट के खुदाई की मंजूरी की तुलना में 10 गुना अधिक खुदाई की गई थी. यही नहीं इस खुदाई से निकले खनिज को बाद में रेलवे के निर्माण कार्य में इस्तेमाल करना था लेकिन इसे बाजार में बेचा गया .....

ऐसी रिपोर्ट हमारा मीडिया क्यों नहीं, देता समझ मे नही आता !..... सिर्फ वाहवाही करना ही हमारे मीडिया का दायित्व रह गया है क्या ?